

'ओम बिड़ला के ओ.एस.डी. राजीव दत्ता पर लगे मानव तस्करी के आरोपों की जाँच गंभीरता और तीव्रता से करें'

राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में दायर एफ.आई.आर. तथा परिवादों की जाँच ए.डी.जी. (अपराध)

दिनेश एम.एन. के निरीक्षण में की जाए

-रेणु मितल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

नई दिल्ली, 4, अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने ओएसडी राजीव दत्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत के निर्देशनुसार एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

जयपुर राजस्थान उच्च न्यायालय बैचने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता, अर्चना झाला, दिनेश मुझानी व विदेशी राणा पुलिस अधीक्षक अजमेर के खिलाफ अजमेर मिस्ट्रेडे एम.एन. कर्मण एवं याचिकाकर्ता इडवोकेट शेखर मेवाड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर का अनुसंधान हाईकोर्ट ने एडीपी भी तुलित किया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि अजमेर, पाली, बूंदी और कोटा में इस मामले से जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर किया है, परन्तु कोटा में राजनीतिक दबाव के चलते उनकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई।

- अदालत ने अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं को कानूनी सुरक्षा देते हुए कहा कि इनके खिलाफ पुलिस प्रशासन बलपूर्वक या दफ्तरात्मक कार्यवाही नहीं कर सकता, जैसे कि उनकी गिरफ्तारी करना इत्यादि, जब तक अदालत ऐसी कार्यवाही करने की अनुमति नहीं देती या याचिकाकर्ता जाँच में सहयोग नहीं करते।
- याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि अजमेर, पाली, बूंदी और कोटा में इस मामले से जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर किया है, परन्तु कोटा में राजनीतिक दबाव के चलते उनकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई।
- याचिकाकर्ता का कहना है कि कोटा से जयपुर के रास्ते में उनके साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जिसकी भी पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की।

जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की। याचिकाकर्ता का कहना है कि अंजान व्यक्ति ने एफ.आई.आर. के चलते उनके एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की। अधिकारी शेखर मेवाड़ा पर बूंदी में सुनवाई एवं याचिकाकर्ता इडवोकेट शेखर मेवाड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर का अनुसंधान हाईकोर्ट ने एडीपी भी तुलित किया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि अजमेर, पाली, बूंदी और कोटा में इस मामले से एफआईआर हाईकोर्ट ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की।

स्कूल इमारतों की बदहाल स्थिति पर सरकार दो सप्ताह में जवाब दे

जयपुर, 4 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रेस की स्कूलों की इमारतों की बदहाल स्थिति और उनमें संसाधनों के अभाव से जुड़े मामले में केंद्र और राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

जस्टिस महेन्द्र गोविंद और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीट ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंजन पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार को और से संपर्क करने सहित अन्य वकील पेश हुए उन्होंने अदालत

- हाई कोर्ट ने प्रकरण के स्वप्रेरित प्रसंजान की सुनवाई 18 अगस्त को तय की।

से मामले में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस बात को अदालत दो सप्ताह का समय देते हुए प्रकरण की सुनवाई 18 को प्रसंजन पर को तय की।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट की पकलपीट ने गत 28 जुलाई को प्रदेश के सरकारी स्कूलों के जबाबदारी भवनों विप्रवेशण में संसाधनों की कमी को लेकर राज्य सरकार के अदालत के अनुसार, एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

अदालत के अदेश के अनुसार, एफआईआर के अधिवक्ताओं को खंडपीट एवं याचिकाकर्ताओं को खिलाफ प्रसंजन पर क्षमता देती है। इसके अन्यतर उन्हें याचिकाकर्ता को खिलाफ मानव तस्करी में परिवाद अनुसंधान में लंबित है तथा उच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

अदालत के अदेश के अनुसार, अदालत ने याचिकाकर्ता का कहना है कि कोटा से जयपुर के रास्ते में उनके द्वारा कानिलाना हमले की एफआईआर के अनुसंधान हाईकोर्ट ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की।

जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

याचिकाकर्ता का कहना है कि अंजान व्यक्ति ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की। अधिकारी शेखर मेवाड़ा पर बूंदी में सुनवाई एवं याचिकाकर्ता का कहना है कि एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की।

जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

याचिकाकर्ता का कहना है कि अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

याचिकाकर्ता का कहना है कि अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

याचिकाकर्ता का कहना है कि अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

याचिकाकर्ता का कहना है कि अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

याचिकाकर्ता का कहना है कि अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

याचिकाकर्ता का कहना है कि अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

याचिकाकर्ता का कहना है कि अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

याचिकाकर्ता का कहना है कि अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

याचिकाकर्ता का कहना है कि अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

याचिकाकर्ता का कहना है कि अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

याचिकाकर्ता का कहना है कि अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

याचिकाकर्ता का कहना है कि अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

याचिकाकर्ता का कहना है कि अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

याचिकाकर्ता का कहना है कि अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की।

जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवाद दायर साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी

